भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 370
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना

***370. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः**

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किन नवीनतम प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने विशेषकर कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देना' के संबंध में लोक सभा में पूछे गए दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 370 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) भारत सरकार देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने हेतु नवीनतम किस्मों, तकनीकों और पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु कृषि क्षेत्र में कई प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने वर्ष 2014 से अब तक कुल 3053 क्षेत्रीय फसल किस्मों को विकसित, रिलीज़ और अधिसूचित किया है। आई.सी.ए.आर. ने जलवायु-अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और प्रिसिज़न फ़ार्मिंग जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन्स/सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। डिजिटल कृषि मिशन एक प्रमुख पहल है जो बेहतर फसल निगरानी, मिट्टी के प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), बिग डेटा और जियोस्पैशियल डेटा जैसी तकनीकों का उपयोग करती है।

(ख) और (ग) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है, ताकि मुख्य रूप से पानी की अधिक खपत वाली धान की फसल के क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक-अनाज, कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके।

भारत सरकार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के तहत तिलहन जैसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन कर रही है। इसके अलावा, दालों और तिलहनों की खरीद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना के तहत एमएसपी पर की जाती है। अरहर, उड़द और मसूर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 2023-24 से पीएम-आशा योजना की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 100 प्रतिशत खरीद को मंजूरी दी जा रही है। बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) भी देश में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देता है और इस योजना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं।

(घ) वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर राज्य जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) क्रियान्वित किया जा रहा है। दोनों ही योजनाएं जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग तक संपूर्ण समर्थन प्रदान करने पर बल देती हैं। योजनाओं का प्रमुख ध्यान

सप्लाई चेन बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर्स बनाना है। वर्ष 2015-16 से (दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर्स की संख्या और कवर किए गए क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	**क्लस्टर्स की संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर में)**
मध्य प्रदेश	3868	74,960
महाराष्ट्र	2978	66,756
दादरा एवं नगर हवेली	25	500

*****